ड्रग्स सिंडिकेट की गिरफ्त में मध्यप्रदेश !

पटवारी बोले-युवाओं को बना रहे निशाना, नेताओं का संरक्षण

भोपाल,25 जुलाई. प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और उसके बढ़ते नेटवर्क ने कानून-व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीते एक वर्ष में ड्रग्स जब्ती के कई बड़े मामलों के साथ सत्ता से जुड़े चेहरों के नाम सामने आना राज्य की स्थिति को चिंताजनक बना रहा है. अक्टूबर 2024 में भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़ी गई 1,814 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक रही. इसी दौरान दाऊद गैंग से जुड़े 168 करोड़ की ड्रग

फैक्टरी के खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की मौजूदगी का संकेत दिया. वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेशभर से 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चरस, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स बरामद की गईं. सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र-छात्राओं और हाईप्रोफाइल

> प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि नशा कारोबार सत्ता के संरक्षण में फल-फूल रहा है. उन्होंने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के करीबी पर भी ड्रग सिंडिकेट से संबंध का आरोप लगाया और उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की. ड्रग्स सिंडिकेट सोशल मीडिया, पार्टियों और आयोजनों के ज़रिए युवाओं को जाल में फंसा रहा है. कई मामलों में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जहां नशे की हालत में युवतियों के वीडियो बनाकर उन्हें धमकाया गया.

युवाओं को नशे की चेन का हिस्सा बनाया गया.

जुलाई 2025 में एक भाजपा नेता के भाई और भतीजे की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी. आरोप है कि वे ड्रग्स तस्करी और यौन शोषण के मामलों में संलिप्त थे. जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में अन्य नेताओं के भी नाम संदिग्ध भूमिका में सामने आए हैं. लगातार हो रही जब्तियों,

जनता और विपक्ष के सवाल

- क्या मध्यप्रदेश ड्रग माफिया का अड्डा बनता जा रहा है?
- क्या नशे के नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण हासिल है?
- आखिर सरकार और गृह विभाग कब तक चुप बैठेंगे?

अंतरराज्यीय नेटवर्क और राजनीतिक लिंक के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है. न तो किसी मंत्री का बयान आया और न ही प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की सूचना है.

राज्य में फैलते नशे के जाल को लेकर विपक्ष आक्रामक है और जनमानस भी जवाब चाहता है. वक्त की मांग है कि दोषियों पर बिना पक्षपात कार्रवाई हो और युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए.

ड्रग्स जिहाद केस में बड़ा खुलासा

राजधानी भोपाल में सामने आए बहुचर्चित ड्रग्स जिहाद मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं. ताजा मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि मुख्य आरोपी यासीन अहमद की गाड़ी पर मध्यप्रदेश विधानसभा का पास चस्पा था. यह पास पत्रकार सौरभ शर्मा के नाम पर जारी किया गया था.

विधानसभा ने पत्रकार को भेजा नोटिस

इस खुलासे के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सौरभ शर्मा को नोटिस भेजा है. उनसे मामले में विस्तृत पूछताछ की संभावना जताई जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आगामी विधानसभा सत्र के दौरान वाहन एंट्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

तीन दिन पहले हुआ था बड़ा खुलासा

तीन दिन पहले पुलिस ने यासीन अहमद उर्फ मछली और उसके साथी शावर को ड्रग्स सहित गिरफ्तार किया था. इनके मोबाइल में 20 से अधिक लड़कियों के अश्लील वीडियो पाए गए. पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी स्कूल-कॉलेज की हिंदू लड़कियों को पार्टियों में बुलाकर ड्रग्स की लत लगाते थे, फिर बलात्कार कर वीडियो बनाते और ब्लैकमेल करते थे. इसके बाद धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जाता था.

एक नजर में

पुलिया पार करते श्रद्धालु बहे, एक की मौत

शिवपुरी. रतनगढ़ माता के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा गुरुवार को एक हादसे में बदल गई. काली पहाड़ी गांव से करीब 15-20 श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले थे. गुराही नदी की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में चार लोग बह गए. गढरौली के पास नदी पार करते वक्त वंदना लोधी, दिलकिस (16), पूनम (14) और विजयराम लोधी (28) बहाव की चपेट में आ गए. ग्रामीणों की तत्परता से तीन लोगों को रस्सियों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन वंदना लोधी की डूबने से मौत हो गई. कुछ देर बाद उनका शव बरामद कर लिया गया. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बरसात में पुल-पुलियों पर न तो चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं और न ही निगरानी रहती है. ग्रामीणों का कहना है कि श्रद्धालुओं को भी बरसात में ऐसे रास्तों से बचना चाहिए.

दो आईपीएस के तबादले

भोपाल. राज्य सरकार ने शुक्रवार देर शाम भारतीय पुलिस सेवा के दो अफसरों के तबादले किये हैं. आदेश के तहत यांगचेन डोलकर भूटिया सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर को पुलिस अधीक्षक देहात इंदौर पदस्थ किया गया है, वहीं हितिका बंसल पुलिस अधीक्षक देहात इंदौर को सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर पदस्थ किया गया है.

सबका नाम बदले जाने की जरूरत : रामेश्वर

हमीदिया के नाम को लेकर गरमाया विवाद

भोपाल,25 जुलाई. राजधानी में हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है.

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल की बसाहट राजा भोज ने की थी, नवाबों की यहां कोई संपत्ति नहीं थी. राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे. जिन्होंने बड़े तालाब और शहर की नींव रखी.

विधायक मसूद के बयान पर भाजपा का तीखा पलटवार

ड्रग्स, लैंड जिहाद पर सरकार कर रही कार्रवाई

नवाब के नाम पर कोई जागीर या स्थान नहीं होना चाहिए

रामेश्वर शर्मा ने नवाब हमीदुल्लाह को एहसान फरामोश बताते हुए कहा कि जब देश के सभी राजा-महाराजा अपनी रियासतें भारत में विलय कर रहे थे, तब नवाब पीछे हट गए. उन्होंने राजा भोज और रानी कमलापति की संपत्ति हड़प ली और उसका गलत इस्तेमाल किया. ऐसे नवाब के नाम पर कोई जागीर या स्थान नहीं होना चाहिए.

ड्रग्स और लैंड जिहाद पर भी साधा निशाना

शर्मा ने कहा कि ड्रग्स, लैंड जिहाद जैसे मामलों पर सरकार चुन-चुनकर कार्रवाई कर रही है. डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नशा मुक्त मध्यप्रदेश बना रही है और बेटा-बेटियों को नशे से बचाने वालों को जेल भेज रही है.

> **मंत्री बोले देशभक्त नहीं थे नवाब**
>
> स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि भोपाल रियासत ने आजादी के बाद भी तिरंगा नहीं फहराने दिया था. उन्होंने भारत में विलय का विरोध किया और भारतीयों पर गोली चलवाई. ऐसे नवाब के नाम पर कोई इमारत या स्थान नहीं रहना चाहिए.

नगरीय प्रशासन विभाग के लेखापाल को हटाया

भोपाल. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लेखापाल ज्ञानेन्द्र शर्मा को वित्तीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप के कारण पद से हटा दिया गया है. विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ज्ञानेन्द्र शर्मा ने लेखापाल के पद पर रहते हुए बिना सक्षम स्वीकृति और बिना अधिकृत भुगतान आदेश के डीडीओ की लॉगइन आईडी का दुरूपयोग कर भुगतान की कार्यवाही की थी.

जांच में यह संपूर्ण प्रक्रिया वित्तीय नियमों के प्रतिकूल और धोखाधड़ी की श्रेणी में आती है. नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने लेखापाल ज्ञानेन्द्र शर्मा को पद से हटाने संबंधी आदेश जारी किये हैं.

28 जुलाई से होगा मानसून सत्र

पहली पंक्ति में बैठेंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल

10 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट होगा पेश

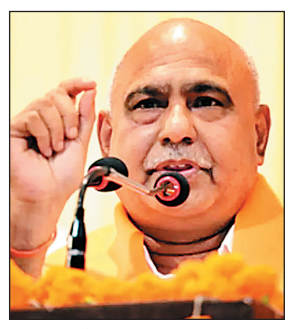

भोपाल, 25 जुलाई. मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पहली पंक्ति में स्थान दिया गया है. यह विधानसभा में उनका कद बढ़ने का संकेत माना जा रहा है.

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, 28 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के लिए विधायकों से अब तक 3377 प्रश्न और 191 ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हो चुकी हैं. सरकार इस सत्र में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश करने वाली है. संभावना है कि यह सत्र काफी गरमाया हुआ रहेगा, जिसमें विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.

हर दूसरा व्यक्ति अपात्र फिर भी लाभ

सिंघार का आरोप : पीडीएस में भारी घोटाला

भोपाल,25 जुलाई.कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि गरीबों का राशन अपात्र लोगों को दिया जा रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकारी आंकड़ों में भी इस अनियमितता की पुष्टि हुई है.

सिंघार के अनुसार प्रदेश में 1.29 करोड़ परिवारों को मुफ्त सरकारी खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के डेटा विश्लेषण में सामने आया है कि इनमें से 64.88 लाख लाभार्थी अपात्र हैं. यानी लगभग हर दूसरा व्यक्ति बिना पात्रता के इस योजना का लाभ ले रहा है.

उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार क्या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगी या अपात्र लोगों की जांच कर उन्हें सूची से हटाएगी और असली जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाएगी? सिंघार ने सरकार से इस विषय पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

> उन्होंने आरोप लगाया कि इन अपात्रों में वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक है, और 17,901 कंपनी संचालक भी मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि कई गरीब आदिवासी मजदूरों के हाथ के अंगूठे के निशान मिट जाने के कारण वे पात्र होने के बावजूद राशन से वंचित हो जाते हैं.

रातापानी टाइगर रिजर्व उद्घाटन पर एक घंटे में 27 लाख की फिजूलखर्ची!

भोपाल. मध्यप्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व के उद्घाटन समारोह पर एक घंटे के कार्यक्रम में 27 लाख रुपये खर्च कर दिए गए. यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त कर सार्वजनिक की है. दुबे के मुताबिक कार्यक्रम में 11.5 लाख रुपये केवल खानपान पर, 2.36 लाख हेलमेट पर, और 7 लाख रुपये पेट्रोल पर खर्च किए गए. इस खर्च को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है और इसमें वन विभाग की मिलीभगत हो सकती है.

आज से चलेगी मप्र की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन

उज्जैन, 25 जुलाई. प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है. मध्यप्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन पातालपानी-कालाकुंड को रेल प्रशासन आज से पुन: शुरू करने जा रहा है.

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए इस हेरिटेज रूट पर फिर से सेवाएं बहाल की हैं. यह ट्रेन इंदौर के पास महू तहसील के घने जंगलों, ऊँच-नीची पहाड़ियों,झरनों और पक्षियों की चहचहाहट से भरपूर रास्तों से होकर गुजरती है. यात्रा के दौरान यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय अनुभव होता है,जो खासकर शनिवार और रविवार को उपलब्ध रहेगा.

पातालपानी-कालाकुंड के बीच चलेगी ट्रेन

यात्रा का समय और सुविधा

रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना के अनुसार ट्रेन संख्या 52965 पातालपानी से सुबह 11.05 बजे चलकर दोपहर 1.05 बजे कालाकुंड पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 52966 दोपहर 3.34 बजे कालाकुंड से चलकर शाम 4.30 बजे पातालपानी लौटेगी. इस ट्रेन में कुल 5 कोच होंगे 2 एसी चेयरकार और 3 नॉन एसी चेयरकार, ताकि विभिन्न वर्गों के यात्री इसका लाभ उठा सकें. पातालपानी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को सड़क मार्ग का उपयोग करना होगा. रेल प्रशासन को उम्मीद है कि यह हेरिटेज ट्रेन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी संबल प्रदान करेगी.

अमरकंटक में बनेगा पेशा एक्ट का केंद्र

केंद्र की स्थापना के लिये हुआ त्रि-पक्षीय एमओयू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 जुलाई.प्रदेश में पेसा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अमरकंटक में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी अमर कंटक के बीच गुरुवार को त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ.

समझौता ज्ञापन मप्र जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी भोपाल में हुआ. त्रि-पक्षीय ज्ञापन समारोह में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव मुक्ता शेखर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मप्र दीपाली रस्तोगी, संचालक सह-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय छोटे सिंह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से कुलपति व्योमकेश त्रिपाठी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण अश्रम के गिरीश कुबेर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति आयोग भारत सरकार हर्ष चौहान, सलाहकार बोर्ड सदस्य निशा, संयुक्त प्रबंध निदेशक ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउडेशन के अनीश कुमार, सहित प्रदेश के विभिन्न पेसा कानून वाले जिलों सरपंच मौजूद थे.

मप्र जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी भोपाल में आयोजित त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन समारोह के दौरान पेसा कानून की पहल सशक्तता और स्वशासन की कहानियां पुस्तिका का विमोचन भी किया गया. इस दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा की यह त्रि-पक्षीय समझौता अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम है. जनजातियों में यदि विवाद होते हैं तो उनका वे आसानी से निपटारा कर लेते हैं. विवादों का समाधान करने की जो प्रक्रिया है, उसे बाकी लोगों को भी सीखने की जरूरत है.

चालक को पीटने का वीडियो वायरल, आरक्षक निलंबित

शिवपुरी. जिले में पदस्थ आरक्षक सोनू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वायरल वीडियो में आरक्षक एक वाहन चालक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है. यह वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था, जिसमें आरक्षक की बदसलूकी साफ दिखाई दे रही थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक सोनू यादव को सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. पुलिस विभाग ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में फिर मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय, बांधों के गेट खुले

भोपाल,25 जुलाई. मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हो गया है. इससे प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी है.

शुक्रवार को राज्य के 19 जिलों में अति भारी और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके चलते कई जगह नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बांधों के गेट खोलने पड़े हैं.

अशोकनगर, विदिशा और शिवपुरी में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए. रायसेन में 2.3 इंच, सिवनी में 1.6 इंच, पचमढ़ी में 1.5 इंच, भोपाल में सवा इंच और दतिया, सागर, शिवपुरी में आधा इंच बारिश दर्ज की गई. शिवपुरी के मड़ीखेड़ा बांध के दो गेट और रायसेन के बारना डैम के चार गेट खोलकर दस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया. मौसम विभाग ने जबलपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत 19 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 8 इंच से ज्यादा पानी गिरने की संभावना है.

> ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर,अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, खंडवा, हरदा, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी समेत 18 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी है. मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में चार वेदर सिस्टम सक्रिय हैं- दो ट्रफ, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक मानसून ट्रफ लाइन,जो प्रदेश के उत्तरी भागों से गुजर रही है. इसके चलते बारिश की तीव्रता चार दिनों तक बनी रहेगी.

नई व्यवस्था | विधानसभा सचिवालय ने सभी मंत्री, विधायकों को लिखा पत्र

विस परिसर में धरना-प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे विधायक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 जुलाई. मध्यप्रदेश विधानसभा में ऐसा पहली बार होगा कि जब विधायक विधानसभा परिसर में धरना, प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं कर पाएंगे.

विधानसभा के मानसून सत्र में इस पर सख्ती रहेगी. इसे लेकर मप्र विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को पत्र भेजा है. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94-2 का हवाला दिया गया है. सामान्य तौर पर सदन के अंदर पत्र और विपक्ष के बीच गतिरोध बनने के बाद विपक्ष वाकआउट कर देता है. उसके बाद विधानसभा परिसर में आकर नारेबाजी करते हैं. वहीं कई बार वे प्रदर्शन भी करते हैं. ये प्रदर्शन न सिर्फ सदन के प्रवेश द्वार के पास बल्कि कई बार विधानसभा परिसर में ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन करते हैं. पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने ही धरना दे दिया था, वे तीन दिन से भी अधिक समय तक धरना देते रहे. यहां तक कि सत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भी वे धरने पर बैठे रहे. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा भी दिलाया था कि उनकी मांगों को लेकर उचित कार्रवाई होगी. आखिरकार सत्रावसान के देर रात मंत्री विश्वास सारंग के लंबे मान- मनौव्वल के बाद उन्होंने देर रात धरना प्रदर्शन समाप्त किया था. विधानसभा सचिवालय ने बीते 10 जुलाई को मंत्री, विधायको को जो पत्र भेजा है, उसमें उनकी सुरक्षा के लिये ऐसा करना जरुरी बताया गया है और व्यवस्था बनाने में सहयोग भी मांगा गया है. विधायकों को नसीहत देते हुए कहा गया है कि वे अपने साथ एक निज सहायक, वाहन चालक का नाम, वाहन नंबर के साथ प्रवेश पत्र कार्यालय को देना सुनिश्चित करें.

विधायकों को ये भी कहा गया है कि वे सत्र के दौरान विधानसभा भवन में किसी गैर या बिना प्रवेश पत्र धारी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में बिठाकर या पैदल विधानसभा परिसर या सदन की लॉबी में प्रवेश नहीं करायें. पहले की तरह सभी मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों के साथ ही बड़े हथियार धारी अंगरक्षकों का सत्र के दौरान प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

> **जनता की आवाज दबाने का प्रयास : सिंघार**
>
> इधर विधानसभा परिसर में विधायकों के प्रदर्शन पर रोक मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर के अंदर प्रदर्शन करने और जनता की आवाज उठाने पर विधायकों को रोक लगाई है. दरअसल, विपक्ष लगातार विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही को लाइव करने की मांग कर रहा है. इसके उलट, विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में अब विधायकों को जनता के मुद्दे उठाने से भी रोक रहे हैं. यह बात याद दिलाने योग्य है कि संविधान की धारा 194 विधायकों को विशेष शक्तियां देता है, जिसका इस्तेमाल कर वे जनता के हित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं. विधानसभा में झूठे एवं फर्जी आंकड़े देने वाली सरकार खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए अध्यक्ष पर दबाव बनाकर इस तरह के नियम और फरमान जारी करवा रही है. यह लोकतंत्र की हत्या है.

वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत

शिवपुरी,25 जुलाई. मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में शुक्रवार को एक तेंदुए का शव सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया. आशंका जताई जा रही है कि यह तेंदुआ किसी वाहन की चपेट में आने से मारा गया है. घटना शिवपुरी शहर की थीम रोड पर गुना नाके के आगे की है.

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह एक तेंदुआ मृत अवस्था में सड़क किनारे पाया गया. प्रथम दृष्टया अनुमान है कि तेंदुआ सड़क पार कर रहा था,तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी पहले भी देखी गई है. वन क्षेत्र से सटे होने के कारण अक्सर जंगली जानवर यहां घूमते नजर आते हैं. तेंदुए की मौत ने वन्यजीव सुरक्षा और रिहायशी इलाकों से सटे जंगलों में वाहनों की गति पर नियंत्रण की जरूरत को फिर से रेखांकित कर दिया है.